गुनौर के नवनिर्मित सहकारी शाखा भवन का हुआ लोकार्पण

प्रशासक ने कहा सहकारिता विभाग किसानों का सच्चा हितैषी

नवभारत न्यूज

पन्ना, 15 सितंबर। गत दिवस पन्ना जिले के गुनौर तहसील मुख्यालय में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा का उद्घाटन मध्यप्रदेश अपेक्स बैंक के प्रशासक महेन्द्र सिंह यादव के मुख्य आतिथ्य तथा बैंक के कोर्ट कमिश्नर न्यायमूर्ति एसएस झा की अध्यक्षता तथा क्षेत्रीय विधायक राजेश वर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ।

बैंक के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक भोपाल के प्रशासक महेन्द्र सिंह यादव ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ सभी किसानों को मिलता है तथा सहकारिता एक आंदोलन है जिसके माध्यम से किसानों को खाद, बीज, कृषि यंत्र एवं उपभोक्ता सामाग्री का वितरण सब कुछ मिलता है जो कि किसानों का सच्चा हितैषी है। उन्होंने कहा कि गुनौर का भवन एक वर्ष के अंदर बना दिया गया यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि निर्धारित समय पर काम कम ही हो पाते हैं उन्होंने इसके लिए बैंक जी.एम. एस.के.कनौजिया की प्रशंसा की। कार्यक्रम में गुनौर विधायक डॉ. राजेश वर्मा ने भी सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता के माध्यम से किसानों को बड़े पैमाने पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है तथा हमारी सरकार द्वारा बिना ब्याज के ऋण दिया जा रहा है। देश में ऐसा कोई बैंक नहीं है जो ऋण के बदले ब्याज न लेता हो। सहकारी बैंक ही एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष के अंदर गुनौर शाखा भवन का निर्माण हो गया इसके लिए पन्ना सहकारिता विभाग एवं ठेकेदार दोनों प्रशंसा के पात्र हैं। मालूम हो कि सन् 2006 में तत्कालीन कलेक्टर व सहकारी बैंक अध्यक्ष दीपाली रस्तोगी के द्वारा गुनौर बैंक शाखा भवन के लिए 272 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन किया गया था उस समय भी पन्ना जिला सहकारी बैंक के जी.एम. एस.के. कनौजिया थे तथा यह भूमि आवंटित कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी तथा वर्तमान में जब भवन का लोकार्पण हुआ उस समय भी श्री कनौजिया पन्ना जिला सहकारी बैंक के जी.एम. हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उक्त भूमि पर कुछ लोगो द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया था जिसको हटाना टेढ़ी खीर थी तथा इसके पूर्व सहकारी विभाग के ब्रांच मैनेजर द्वारा कब्जा हटाने का प्रयास किया गया लेकिन अधिकारियों का सहयोग न मिलने के कारण नहीं हटा पाए थे।

श्री कनौजिया 2023 में जब पुन: पन्ना पदस्थ हुए उन्होंने इस ओर ध्यान दिया तथा 2025 में तत्कालीन कलेक्टर सुरेश कुमार से पहल कर बेजा कब्जा हटवा दिया तथा 01 वर्ष के अंदर भवन बनकर तैयार हो गया तथा अब लोकार्पण भी हो गया। उक्त भवन को मूर्त रूप देने में इंजीनियर एवं शाखा प्रबंधक राजेन्द्र मिश्रा का भी महत्वपूर्ण योगदान है जिन्होंने तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर डी.पी.आर. बनाकर निविदा आमंत्रित कर कार्य प्रारंभ करवाया। लोकार्पण कार्यक्रम में कोर्ट कमिश्नर एस.एस. झा उपस्थित रहे उन्हीं की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ। उक्त कार्यक्रम में जी.एम. एस.के. कनौजिया, भाजपा नेता रविराज सिंह यादव, गुनौर नगर पंचायत अध्यक्ष अर्चना मलखान सिंह, लेखाधिकारी अमन सिंह, ब्रांच मैनेजर राजेन्द्र मिश्रा, अमित श्रीवास्तव, जे.एन. पाठक, कौशलेन्द्र पाण्डेय, सुरेन्द्र द्विवेदी, अमोल सिंह, मनीष पाण्डेय आदि सभी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के शाखा प्रबंधक व जिले के सभी समिति प्रबंधक उपस्थित रहे।

वायरल बुखार ने बढ़ाई बेचैनी बुखार उतरा तो खांसी ने घेरा

नवभारत न्यूज

पन्ना, 15 सितंबर। मौसम में उतार-चढ़ाव के साथ शहर में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। घर-घर लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी से लेकर निजी चिकित्सकों के क्लीनिक तक मरीजों की भीड़ उमड़ रही है।

सबसे ज्यादा चिंता उन मरीजों को लेकर है, जिनका बुखार तो कुछ दिनों में ठीक हो जा रहा है, लेकिन खांसी कई सप्ताह तक पीछा नहीं छोड़ रही। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में सर्दी-जुकाम और खांसी की शिकायत सामने आ रही है। कई मरीज ऐसे भी अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिन्हें बुखार के साथ गले में खराश, बदन दर्द और कमजोरी की समस्या है। लगातार खांसने के कारण कई मरीजों को सीने और गले में दर्द की शिकायत भी हो रही है।

चिकित्सकों के पास पहुंचने वाले मरीजों में वायरल संक्रमण से जुड़े लक्षण प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। चिकित्सक लक्षणों के आधार पर उपचार के साथ जरूरत पड़ने पर जांच की सलाह दे रहे हैं।

बच्चों और बुजुर्गों का रखें विशेष ध्यान - मौसम बदलने के दौरान बच्चों और बुजुर्गों में संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। चिकित्सकों ने साफ-सफाई का ध्यान रखने, पर्याप्त पानी पीने, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सावधानी बरतने और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। बिना चिकित्सीय सलाह के एंटीबायोटिक या अन्य दवाओं का सेवन न करने की भी सलाह दी जा रही है।

जिला अस्पताल में जांचे हुईं दोगुनी

संक्रमण के बढ़ते मामलों का असर जिला अस्पताल की पैथोलॉजी पर भी दिखाई दे रहा है। ओपीडी में आने वाले मरीजों की चिकित्सीय जरूरत के अनुसार जांच कराई जा रही है। इसके चलते पैथोलॉजी विभाग में जांच कराने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। सुबह से ही मरीज और तीमारदार कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। जांच रिपोर्ट के लिए भी मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है। ओपीडी पर बढ़ा मरीजों का दबाव संक्रमण के मामले बढ़ने से जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों का दबाव बढ़ गया है। सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। निजी अस्पतालों और क्लीनिकों में भी यही स्थिति बनी हुई है। चिकित्सकों के यहां सामान्य दिनों की तुलना में वायरल लक्षण वाले मरीज अधिक पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि वायरल संक्रमण के बाद कुछ समय तक खांसी बनी रह सकती है। हालांकि, यदि खांसी लगातार बनी रहे या उसकी तीव्रता बढ़ती जाए तो इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, लगातार तेज बुखार, अत्यधिक कमजोरी या अन्य गंभीर लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सीय सलाह लेना जरूरी है।

जनपद सदस्य का निर्वाचन निर्विरोध तय

जिगनी में सरपंच पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में

नवभारत न्यूज

अजयगढ़, 15 सितंबर। अजयगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है।

नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 9 से केवल एक ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जबकि जिगनी ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए 4 अभ्यर्थियों ने अपने फॉर्म जमा किए हैं। वार्ड क्रमांक 9 से केवल एक ही नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है, जो पूर्व जनपद सदस्य की पत्नी द्वारा दाखिल किया गया है।

नियमानुसार, फॉर्म की संवीक्षा (जांच) सही पाए जाने पर रिटर्निंग ऑफिसर एवं तहसीलदार सुरेंद्र कुमार द्वारा उन्हें निर्विरोध जनपद सदस्य घोषित कर दिया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर सुरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने की समय-सीमा आज दोपहर 3 बजे समाप्त हो चुकी है। अब जमा किए गए आवेदनों की जांच की जाएगी और अभ्यर्थियों को उनके निर्वाचन प्रतीक चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

स्थानीय सब्जी की आवक न होने से बाहरी मंडियों के भरोसे व्यापारी

नवभारत न्यूज

पन्ना, 15 सितंबर। जिले में बारिश के कारण सब्जियों की स्थानीय आवक प्रभावित हुई है। खेतों में जलभराव से जहां कई फसलों को नुकसान पहुंचा है, वहीं कटाई और परिवहन में भी दिक्कतें बढ़ गई हैं।

दूसरी ओर आसपास के शहरों और थोक मंडियों से पर्याप्त मात्रा में सब्जियां नहीं पहुंच पाने के कारण फुटकर बाजार में दाम लगातार चढ़ रहे हैं। कई सब्जियों के भाव पिछले दिनों की तुलना में काफी बढ़ गए हैं। महंगी सब्जियों ने गृहिणियों के घरेलू बजट का हिसाब भी बिगाड़ दिया है। सबसे अधिक महगांई का असर प्याज, लहसुन, अदरक आदि में देखा जा रहा है।

खेतो में जलभराव से समस्या - सब्जी व्यापारियों के मुताबिक लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है। इसका असर सब्जियों की फसल पर पड़ रहा है। कई स्थानों पर तैयार फसल खराब होने की स्थिति में हैं, जहां सब्जियां उपलब्ध हैं, वहां बारिश के कारण उनकी कटाई मुश्किल हो रही है। खेत से मंडी और मंडी से बाजार तक सब्जियां पहुंचाने में समय और लागत दोनों बढ़ रहे हैं। आवक कम होने के बाद बाजार की निर्भरता बाहरी मंडियों पर बढ़ गई है। खराब मौसम के चलते वहां से भी नियमित और पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उपलब्धता कम होने का सीधा असर फुटकर कीमतों पर दिखाई दे रहा है। फुटकर बाजार में इस समय आलू 20 रुपए, प्याज 60 रुपए और टमाटर 40 रुपए किलो बिक रहा है। भिंडी, तोरई और खीरे के भाव भी 40 रुपए किलो हैं। नींबू और मूली 5 रुपए प्रति नग मिल रही है। वहीं रसोई में रोजाना इस्तेमाल होने वाला धनिया 250 रुपए किलो तक पहुंच गया है। चुकंदर, गाजर, परवल, करेला और बरबटी के भाव 60 रुपए किलो हैं। लौकी 10 रुपए किलो और कद्दू 30 रुपए किलो बिक रहा है। गोभी 40 रुपए प्रति नग है।

सीमित खरीददारी को मजबूर परिवार

सब्जियों के बढ़ते दाम का सबसे ज्यादा असर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर पड़ रहा है। गृहिणियों का कहना है कि पहले सप्ताह में कई तरह की हरी सब्जियां आसानी से खरीद ली जाती थीं, लेकिन अब कीमतें बढ़ने के कारण मात्रा कम करनी पड़ रही है। परिवारों ने महंगी सब्जियों की जगह अपेक्षाकृत सस्ती सब्जियों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। एक साथ कई सब्जियां खरीदने के बजाय लोग जरूरत के हिसाब से थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं।

उप चुनाव में ऑब्जर्वर ने मतदान केंद्र स्ट्रांगरूम का किया निरीक्षण

नवभारत न्यूज

अजयगढ़, 15 सितंबर। जनपद पंचायत अजयगढ़ के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 के जनपद सदस्य एवं ग्राम पंचायत जिगनी के सरपंच पद के लिए होने वाले उप-चुनाव की तैयारियाँ तेज़ हो गई हैं।

मंगलवार को निर्वाचन प्रेक्षक (ऑब्जर्वर) डी.पी. द्विवेदी ने क्षेत्र के 8 मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके उपरांत प्रेक्षक ने तहसील कार्यालय परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम एवं तहसील निर्वाचन कार्यालय का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी सुरेंद्र कुमार के साथ चुनाव तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की और स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के समय जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) सहित जनपद एवं तहसील के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

आईटीआई कॉलेज की 15वर्षों से सड़क बदहाल

नवभारत न्यूज

पन्ना, 15 सितंबर। आईटीआई भवन बने लगभग 15 साल होने जा रहा है लेकिन आज भी पहुंच मार्ग के लिये मोहताज है। पहली नजर में देखकर लगता है जैसे किसी खेत का कच्चा रास्ता हो बारिश के बाद कीचड़ और दलदल से होकर रोजाना करीब 300 विद्यार्थी अपने भविष्य को संवारने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पहुंचते हैं।

सड़क पर जमा पानी, कीचड़ और गहरे गड्ढों के निशान विद्यार्थियों की मुश्किलें साफबयां कर रहे हैं। बारिश होते ही यह रास्ता विद्यार्थियों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं रहता। पैदल आने वाले विद्यार्थियों को कीचड़ से बचते हुए कदम बढ़ाने पड़ते हैं, जबकि दोपहिया वाहनों से आने वालों के सामने फिसलने का खतरा बना रहता है। कई स्थानों पर रास्ते में इतना कीचड़ है कि वाहन निकालना भी मुश्किल नजर आता है। जूते-कीचड़ से सन जाते हैं और कपड़ों पर छींटें पड़ना आम बात हो गई है। इससे विद्यार्थी बहुत परेशान हैं।

बच्चे ही नहीं राहवासी-किसान भी परेशान - रास्ते की बदहाली से केवल विद्यार्थी ही नहीं बल्कि के रहवासी समेत कृषि विज्ञान केंद्र का स्टाफ, यहां आने-जाने वाले किसान भी परेशान हैं। दोनों ओर उगी झाड़ियां और बीच में कीचड़ से भरा रास्ता देखकर सहज ही सवाल उठता है।

प्रवेश लेने से कतराते हैं विद्यार्थी

एक तरफयुवा वर्ग को कौशल विकास से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफउन्हें प्रशिक्षण संस्थान तक पहुंचने के लिए मूलभूत सुविधा के अभाव से जूझना पड़ रहा है। हालत यह है कि विद्यार्थी पन्ना आईटीआई में प्रवेश लेने से कतराते हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि बारिश के मौसम में रास्ते की हालत सबसे ज्यादा खराब हो जाती है। यदि समय रहते मार्ग का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो किसी दिन फिसलने से गंभीर हादसा भी हो सकता है।

एबीव्हीपी ने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

नवभारत न्यूज

पन्ना, 15 सितंबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत के प्रांत महामंत्री सुव्रत भजल के नेतृत्व में छात्रसंघ चुनाव पुन: बहाल करने की मांग को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में छात्रसंघ चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन मध्यप्रदेश में वर्ष 2017 से छात्रसंघ चुनाव बंद हैं। इसके कारण प्रदेश के लाखों विद्यार्थी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। परिषद ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक चेतना एवं संगठनात्मक कौशल के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। छात्रसंघ विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम बनकर विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि उच्च न्यायालय के निर्देशों एवं लिंगदोह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर शीघ्र ही प्रत्यक्ष, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध छात्रसंघ चुनाव आयोजित किए जाएं।

एसडीएम की कार्यप्रणाली को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत ग्रामीणों ने उठाए सवाल

नवभारत न्यूज

पवई 15 सितम्बर। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व समीक्षा जैन की कार्यप्रणाली को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष निधि पटेरिया सहित क्षेत्र के ग्रामीणों एवं आमजन ने सवाल उठाए हैं।

मामले को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं अधिवक्ता संघ और सामाजिक संघठनों नें रविवार कों प्रवास पर आये प्रभारी मंत्री इंदल सिंह परमार के नाम ज्ञापन सौंपकर एसडीएम कार्यालय की कार्यप्रणाली की उच्चस्तरीय जांच कराने तथा आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। जिस पर प्रभारी मंत्री नें कार्यवाही का अश्वासन दिया है।वहीं कुछ दिन पूर्व ग्रामीणों ने विधायक प्रहलाद सिंह पटेल के नाम भी शिकायत पत्र सौंपा है एवं जानकारी अनुसार विधायक प्रहलाद लोधी नें प्रभारी मंत्री कों पत्र लिख कर एसडीएम पवई कों हटाने की मांग की है।भाजपा मंडल अध्यक्ष निधि पटेरिया द्वारा 13 सितंबर को दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि एसडीएम कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर जनता एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों में असंतोष व्याप्त है।ज्ञापन में राजस्व कार्यों में लापरवाहीए नामांतरणए सीमांकनए बंटवारा एवं नामांतरण की फाइलों के लंबे समय तक लंबित रहने का आरोप लगाया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि मंडल के पार्टी कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जनहित की समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखे जाने के बावजूद अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता। साथ ही क्षेत्र में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्योंए अतिक्रमण हटाने एवं राहत कार्यों में प्रशासनिक स्तर पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए जाने की शिकायत भी की गई है। इधरए ग्रामीणों द्वारा विधायक के नाम सौंपे गए शिकायत पत्र में एसडीएम पर कार्यप्रणाली में उदासीनता और आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनहीन व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व संबंधी मामलों में लोगों को बार.बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। शिकायत में सीमांकनए नामांतरणए बंटवारा और अन्य राजस्व प्रकरणों के लंबित होने का भी उल्लेख किया गया है।

समग्र आईडी सुधार के लिए गांव से लेकर तहसील एवं जिला तक की दौड़

नवभारत न्यूज

पन्ना, 15 सितंबर। एक समय पर पर समग्र को लेकर इतनी तेजी से काम चला कि पंचायत स्तर पर ही कोई भी व्यक्ति अपनी आईडी जनरेट करवा लेता था। किन्तु वर्तमान समय पर समग्र आईडी बनवाना या उसमें सुधार करवाना आसान नहीं है।

उसकी प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया गया है कि इसके लिये आवेदकों को पंचायत स्तर से आवेदन करने के बाद तहसील से लेकर जिले तक की यात्रा करनी पड़ती है। अंत में कलेक्टर की आईडी से स्वीकृति मिलने के बाद ही सुधार हो सकता है अथवा नई आईडी बन सकती है।

दिन भर आते हैं कई मामले - कई लोग जो अपनी अलग आईडी चाहते हैं जो अपनी समग्र आईडी में कोई सुधार करना चाहते हैं उन्हें आवेदन करने के बाद पंचायत, व जनपद होत हुये जिले तक आना पड़ता है। कई स्तर से प्रकरण में परीक्षण एवं अनुशंसा के बाद ही जिला स्तर से अनुमति मिलती है।

कई लोगों ने किया दुरुपयोग

संयुक्त परिवार में जो लोग रहते थे उनकी एक परिवार आईडी बनाई जाती थी। ऐसा नियम व निर्देश भी थे। किन्तु जैसे ही लोगों को पता चला कि परिवार आईडी एक होने से सभी लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता तो खेल शुरू हो गया। जहां भले ही संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग भौतिक रूप से एक साथ रहते हों किन्तु वहां पिता की अलग परिवार आईडी, पुत्र की अलग परिवार आईडी, भाई की अलग परिवार आईडी तैयार होनी शुरू हो गई। इस तरह से परिवार आईडी की संख्या इतनी अधिक हो गई कि बाद में इस मामले पर सरकार को कड़ाई करनी पड़ी। लिहाजा अब समग्र आईडी से संबंधित मामले में नीचे से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के आधार पर ही कोई सुधार या नई आईडी जनरेट हो सकती है। उसके लिये जिले के कलेक्टर आवेदक को दौड़ लगानी पड़ती है।

सात जुआंरी गिरफ्तार

पन्ना, 15 सितंबर। पन्ना जिले में अवैध जुआ और सट्टा गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना देवेन्द्रनगर पुलिस को चांदा हार नाला के पास बड़े पैमाने पर जुआ खेले जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर दबिश दी। पुलिस टीम ने मौके से ताश के पत्तों पर हार-जीत की बाजी लगा रहे सात आरोपियों को रंगे हाथों धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में ग्राम बड़वारा निवासी शैलेन्द्र उर्फराजा शुक्ला एवं प्रदीप उर्फमटरू शर्मा, देवेन्द्रनगर के कंजड़ाना मोहल्ला निवासी अर्जुन सिसोदिया, गोपी सिसोदिया एवं अनिल सिसोदिया, तथा ग्राम भिलसांय निवासी नागेन्द्र द्विवेदी एवं जयहिन्द सिंह शामिल हैं।

मझगांय बांध पर जल-चिता आंदोलन के चौथे दिन गरमाई सियासत, विस्थापितों ने उठाई न्याय की मांग

नवभारत न्यूज

पन्ना, 15 सितंबर। केन-बेतवा लिंक परियोजना सहित मझगांय बांध, रुंझ बांध और सिंगरौली-ललितपुर रेलवे लाइन से प्रभावित विस्थापितों का चिता आंदोलन आज चौथे दिन भी जारी रहा। आंदोलन में प्रभावित परिवारों के साथ बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर शामिल हुईं।

डूबते गांवों और बढ़ते जलस्तर के बीच प्रभावित लोग पानी में चिताओं पर लेटकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जय किसान संगठन के नेता अमित भटनागर ने कहा कि जब इन परियोजनाओं की शुरुआत हुई थी, तब प्रभावित लोगों ने विकास का विरोध नहीं किया था। उन्होंने केवल ग्रामसभा, पारदर्शिता, कानून के पालन, उचित मुआवजे और सम्मानजनक पुनर्वास की मांग की थी। लेकिन प्रभावितों का आरोप है कि उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया गया और कई मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना उनकी जमीन और संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। अमित भटनागर ने कहा कि जब प्रभावित लोगों ने धरना-प्रदर्शन शुरू किया तो धारा 144 और वर्तमान में लागू धारा 163 जैसी निषेधात्मक कार्रवाइयों के माध्यम से आंदोलन को रोकने का प्रयास किया गया। आंदोलन तेज होने पर आंदोलनकारियों पर मुकदमे लगाए गए। इसके बावजूद प्रभावित परिवार अपनी मांगों को लेकर लगातार लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करते रहे। उन्होंने कहा कि आज स्थिति बेहद गंभीर है विकास के नाम पर विस्थापित आदिवासी किसानों के घर और गांव पुलिसिया दमन के माध्यम से बुलडोज कर दिए गए, उनके घर पानी में डूब चुके हैं, कई गांवों में पानी पहुंच चुका है और कुछ घर लगातार गिर रहे हैं,

लेकिन अनेक प्रभावित परिवारों को अभी तक उनका मुआवजा नहीं मिला है। उनका कहना है कि बिना उचित मुआवजा और पुनर्वास के लोगों के घरों और गांवों को डुबाना गंभीर मानवीय और कानूनी सवाल खड़ा करता है।

5 लाख से 12.50 लाख के पुनर्वास पैकेज तक, फिर भी भुगतान का इंतजार - आंदोलनकारियों के अनुसार पहले प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास पैकेज 5 लाख था। जुलाई में हुए चिता आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट में प्रभावित परिवारों के लिए 12.50 लाख के पैकेज का निर्णय घोषित किए जाने की बात सामने आई थी। इसके बावजूद आंदोलनकारियों का आरोप है कि अभी तक कई परिवारों को बढ़ा हुआ पैकेज तो दूर, पहले निर्धारित 5 लाख की राशि भी नहीं मिली है। प्रभावित किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी जमीनों के रिकॉर्ड में सिंचित भूमि को असिंचित कर दिया गया, जिससे मुआवजे की राशि प्रभावित हुई, लेकिन इस अंतर की राशि भी उन्हें नहीं दी गई।

कई परिवारों के मकान और जमीन का मुआवजा भी लंबित बताया जा रहा है। एक तरफ सरकार परियोजना का काम आगे बढ़ा रही है और दूसरी तरफ प्रभावित परिवारों के घर पानी में डूब रहे हैं। जिन लोगों को पहले मुआवजा और पुनर्वास मिलना चाहिए था, वे आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह केवल मुआवजे का सवाल नहीं है, बल्कि संविधान, कानून, जीवन, गरिमा और न्याय के अधिकारों का सवाल है।

कई परियोजनाओं के प्रभावित एक मंच पर

चिता आंदोलन में केवल केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित लोग ही नहीं, बल्कि मझगाय बांध, रुंझ बांध और सिंगरौली-ललितपुर रेलवे लाइन से प्रभावित लोग भी शामिल हुए। प्रभावितों ने अपनी समस्याएं साझा करते हुए कहा कि परियोजनाएं अलग-अलग हैं, लेकिन विस्थापन, मुआवजा और पुनर्वास से जुड़ी उनकी पीड़ा समान है। उन्होंने कहा कि पहले जल, जंगल, जमीन छीनी गई, फिर घर और गांव डुबो दिए गए। जब लोग न्याय मांगने सड़क पर आए तो निषेधाज्ञा और मुकदमों का सामना करना पड़ा और अब हमारे आरोप के अनुसार बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी रोकी जा रही हैं। आखिर यह कैसा विकास है?

न्याय दो या मार दो, विस्थापितों में आक्रोश

अमित भटनागर ने कहा कि चिता आंदोलन का नारा न्याय दो या मार दो विस्थापित परिवारों की बेबसी और आक्रोश को व्यक्त करता है। उन्होंने कहा, हम सरकार से पूछ रहे हैं कि अगर हमें न्याय नहीं देना है तो क्या सरकार ने यह तय कर लिया है कि हमें मार दिया जाए? इस तरह घर, जमीन, गांव और जड़ों से उखाड़कर दर-दर भटकाने से अच्छा है कि सरकार हमारी पीड़ा को समझे और न्याय दे। हम मौत नहीं मांग रहे हैं, हम न्याय मांग रहे हैं। हमें उचित मुआवजा, सम्मानजनक पुनर्वास और हमारे संवैधानिक व कानूनी अधिकार चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि डूब क्षेत्र के प्रत्येक प्रभावित परिवार का तत्काल सत्यापन कराया जाए, लंबित मुआवजा दिया जाए, सिंचित-असिंचित भूमि के मूल्यांकन की शिकायतों का निराकरण किया जाए, मकान एवं अन्य परिसंपत्तियों का उचित मूल्यांकन किया जाए तथा घोषित पुनर्वास पैकेज और सभी वैधानिक अधिकार तत्काल दिए जाएं। जब तक विस्थापितों को न्याय नहीं मिलता, चिता आंदोलन जारी रहेगा।